मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन श्रीगंगानगर जिले में गंगनहर परियोजना के अन्तर्गत शिवपुर हैड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम भी पूछी।

‘अंतिम छोर तक भरपूर नहरी पानी पहुँचाने के लिए राज्य सरकार कर रही कार्य’

आईजीएनपी, भाखड़ा नहर और गंगनहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए दोनों बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की लम्बे समय से चली आ रही माँग को पूरा करने के लिये गंगनहर प्रणाली की क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत, सी.पी. लाइनिंग, फीडर पुर्ननिर्माण व ऑटोमेशन के लिये 1195 करोड़ रूपये के कार्य कराये जायेंगे।**

जयपुर/श्रीगंगानगर, 9 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ- श्रीगंगानगर के अपने दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन बुधवार को श्रीगंगानगर जिले में गंगनहर परियोजना के अन्तर्गत शिवपुर हैड का निरीक्षण किया।

निरीक्षण करने के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, ताकि अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक भी पर्याप्त नहरी पानी पहुंचा कर किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में नहरी जल पर निर्भरता को देखते हुए राज्य सरकार ने आईजीएनपी, भाखड़ा नहर और गंगनहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए गत दोनों बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए गंगनहर प्रणाली में क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत, सीसी लाइनिंग, फीडर पुनर्निर्माण, ऑटोमेशन आदि के 1195 करोड़ रुपए के कार्य करवाएं जाएंगे, जिससे सीपेज लॉस में कमी आएगी और किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गंग कैनाल ऐप और गंगनहर रेग्युलेशन पोर्टल का निर्माण भी किया गया है, जिससे नहर खुलने और बंद होने की जानकारी उनके मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेगी।

शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की नहरों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण, पक्के खालों के निर्माण, बैलेन्सिंग रिजर्वायर आदि कार्यों के लिए इस वर्ष के बजट में 1108 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत, नोहर व भादरा तहसीलों में नहरों के जीर्णोद्धार के 128 करोड़ रुपए के कार्य शुरू करवाए जा चुके हैं और 45 करोड़ रुपए के कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाए जाएंगे।

शर्मा शिवपुर हैड स्थित महाराजा गंगासिंह जी की प्रतिमा पर गए तथा संग्रहालय का अवलोकन किया। शर्मा ने गंगनहर तथा शिवपुर हैड के निर्माण में महाराजा गंगासिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को नमन किया। इसके बाद, शर्मा ने शिवपुर हैड के नजदीक आयोजित प्रदर्शनी में बागवानी पद्धति, कृषि यंत्र सहित विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया।

कैशलैस इलाज योजना में देरी, सुप्रीम कोर्ट नाराज

- **सुप्रीम कोर्ट ने देरी के लिए केन्द्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।**

नई दिल्ली, 09 अप्रैल। मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही अदालत ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया। मामले में सुनावई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बातपर आपत्ति जताई कि 8 जनवरी के आदेश के बावजूद केन्द्र सरकार ने इसका अनुपालन नहीं किया।

कोर्ट ने आगे कहा कि 8 जनवरी को दिए गए आदेश के बावजूद केन्द्र ने योजना को लागू नहीं किया, जो कि एक गंभीर उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने इस पर आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि यह न केवल अदालत के आदेश का उल्लंघन है, बल्कि एक लाभकारी कानून को लागू करने में भी देरी हो रही है। अदालत ने केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से कहा कि यह उनका खुद का कानून है और यदि योजना लागू नहीं की जाती तो लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को 28 अप्रैल को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया।

अमेरिका ने 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेजा

तहव्वुर राणा को भारत ला रहा विमान देर रात तक भारत पहुंचेगा

- **भारत से एक विशेष टीम तहव्वुर को लेने अमेरिका गई है।**
- **राणा के भारत आगमन के सम्बंध में बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अहम मीटिंग की।**
- **राणा का विमान कहां लैंड करेगा, उसे कहां रखा जाएगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है**

नयी दिल्ली, 09 अप्रैल। मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तानी तुहव्वुर राणा को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही के लिए अमेरिका से प्रत्यर्पित कर बुधवार को भारत के लिए रवाना किया गया। उसे लाने के लिए भारत से एक विशेष टीम गई है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राणा को एक विशेष विमान से भारत के लिए रवाना कर दिया गया है। राणा को लेकर आ रहे विमान के भारतीय समयानुसार आज देर रात यहां पहुंचने की संभावना है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उसका विमान भारत में कहां उतारा जाएगा और राणा को किस स्थान पर रखा जाएगा। वह शुरू में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में रहेगा, जो कानूनी औपचारिकताएं पूरी करेगा।

तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले हलचल तेज हो गई है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद की रणनीति पर चर्चा के लिए की गई।

इससे पहले अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की उस याचिका को खरिज कर दिया था जिसमें उसने खुद को भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने का विरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसे भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का रास्ता साफ हो गया था।

राणा ने प्रत्यर्पण की कार्रवाई के विरुद्ध 13 फरवरी को दायर याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ अमेरिका में सभी अपीलों पर अदालती कार्यवाही पूरी होने तक उसे भारत को न सौंपा जाए। उसने तर्क दिया कि उसे भारत को प्रत्यर्पित किया जाना अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी संधि का उल्लंघन है। राणा का कहना था कि उसे भारत में यातनाएं दी जा सकती हैं।

अमेरिकी शीर्ष अदालत द्वारा सोमवार को भारत को उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका को खारिज कर दिये जाने के बाद उसे भारत भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत से एक मल्टी-एजेंसी टीम अमेरिका गई थी और उसने अमेरिकी अधिकारियों के साथ सभी कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में मदद की।

रिपोर्टों के अनुसार, 64 वर्षीय पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक राणा, पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी समूह, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। राणा लॉस एंजिल्स में अमेरिकी मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में 14 साल तक कैद रहा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 2023 में भारत को उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, लेकिन उसने शीर्ष अदालत में बार-बार प्रत्यर्पण रोकने के लिए याचिकाएं दायर कीं थीं, पर उसे सफलता नहीं मिली। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने वाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में राणा के भारत में प्रत्यर्पण की घोषणा की थी।

राणा ने आतंकवादी हमले से पहले मुंबई में आतंकी हमलों के स्थानों को चिह्नित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से रेकी और जासूसी की थी, उसने जिहादी साथी दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली को पाकिस्तानी-अमेरिकी पासपोर्ट का उपयोग करके भारत की यात्रा करने में भी मदद की थी।

‘अब दांव पर वाणिज्य और व्यापार नहीं, वरन् ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यदि बीज़िंग पीछे नहीं हटता तो अतिरिक्त 50 प्रतिशत टैरिफ बुधवार तक लागू किया जाएगा। “जैसे को तैसा” की इस प्रक्रिया की शुरुआत पिछले सप्ताह ट्रंप द्वारा चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने से हुई, जिसका चीन ने तुरंत वैसा ही जवाब दिया था। अमेरिकी टैरिफ चीनी सामानों पर औसतन 76 प्रतिशत के करीब पहुंचने वाला है, व्यापार परिदृश्य अब आर्थिक तर्क के बजाय राजनीतिक इच्छा के द्वारा तय किया जा रहा है।

बाजारों ने पहले ही घबराहट भरी प्रतिक्रिया दी है।

हाँगकाँग का हैंगसेंग इंडेक्स सोमवार को सभी को चौंकाते हुए 13.2 प्रतिशत तक गिर गया जो एशियाई वित्तीय संकट के बाद से एक ही दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी, हालांकि मंगलवार को कुछ हद तक सुधार हुआ।

फिर भी कुछ अर्थशास्त्री पूछ रहे हैं: यह स्थिति कब तक रहेगी,

इकोनॉमिस्ट इंटैलिजेंस के वरिष्ठ अर्थशास्त्री शू तियानचेन ने कहा, “चीन पहले से ही 60 प्रतिशत से अधिक के टैरिफ दर का सामना कर रहा है- अगर यह 50 या 500 प्रतिशत तक बढ़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता”, इसके बजाय, शु ने चेतावनी दी, चीन भी इसी तरह से प्रतिशोध ले सकता है।

दांव अब सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं रह गए हैं। बल्कि गर्व, ताकत और विश्व में अपनी स्थिति दर्शाने का जरिया बन गए हैं।

भारत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसके अन्तर्गत बाँग्लादेश ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक एक एयरबेस को नया रुप देने के लिये चीनी सहायता माँगी है। लालमोनिर्हट - स्थित यह एयरबेस, जो चिकन नैक के नाम मशहूर सँकरी सिलीगुड़ी पट्टी के नजदीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिये एक संकटपूर्ण द्वार (क्रिटिकल गेटवे) है। रिपोर्ट बता रही हैं कि बाँग्लादेश इस क्षेत्र में चीन के साथ सामरिक सहयोग की संभावनाएं खँगाल रहा है।

निर्यात सुविधा निरस्त करने के भारत के निर्णय का असर भूटान तथा नेपाल पर भी पड़ सकता है। ये देश लैन्डलॉक्ड (जमीन से घिरे हुये) हैं तथा व्यापारिक पहुँच के लिये पूरी तरह भारत के जमीनी रास्तों पर निर्भर हैं। भारत सरकार का यह निर्णय “जनरल एग्रीमेन्ट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) के अनुच्छेद 5 के परस्पर प्रयोजनों (क्रॉस परपज) से जुड़ा प्रतीत होता है।

लेकिन ये नियम व्यापक रुप से लागू होते हैं तथा ये अप्रतिबद्ध एवं अबाधित (ऐब्सॉल्यूट) नहीं हैं। एक अधिकारी ने बताया कि “कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों का हवाला दिया जा सकता है।” अधिकारी ने आगे कहा: “भारत के लिये यह जरुरी है कि वह अपनी दलीलें विशेषरुप से भूटान और नेपाल समझा दे।

पायलट को और अधिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि जूली कहाँ है, वे यहाँ हैं या नहीं? इस पर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष (जूली) की तलाश हुई, लेकिन वे नहीं मिले, वे संभवत: जा चुके थे। जूली से संबंधित मुद्दे पर राहुल ने कहा, “भाजपा दलितों को मंदिर में नहीं जाने देती है और अगर कोई चला जाये, तो वे मंदिर को धुलवाते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है, जो सबको इज़्ज़त देता है, हर व्यक्ति का आदर करता हैं।”

“कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है, हमारे दिलों में सबके लिये मोहब्बत और इज़्ज़त है, जबकि उनके दिलों में सिर्फ नफ़रत। हम इस देश को नफ़रत का बाज़ार नहीं बनने देंगे- मोहब्बत की दुकान खोलकर न्याय का हिन्दुस्तान बनाएंगे।”

राहुल गांधी ने विधिवत घोषणा की कि उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटियों (डीसीसी) को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। डीसीसी टिकट चयन की प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। डीसीसी के चयन के लिये कुछ गाइडलाइन तैयार की गई हैं।

पार्टी की पहली मीटिंग 15 अप्रेल को अहमदाबाद में तथा दूसरी मीटिंग 28 अप्रेल को जयपुर में होगी। इन मीटिंगों में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे ही, राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी विभिन्न राज्यों में होने वाली इन मीटिंगों में उपस्थित होने की हर संभव कोशिश करेंगे। डीसीसी के चयन के तौर-तरीके और नियम-कायदे तय हो गये हैं तथा गुजरात में होने वाली पहली मीटिंग से इनका क्रियान्वयन शुरु हो जायेगा।

रिज़र्व बैंक ने ब्याज दर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से ब्याज दरों में नरमी के एक चरण की शुरुआत है। यह बात महत्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक के नए गवर्नर, संजय मल्होत्रा ने अपने पॉलिसी स्टेटमैंट में कहा है कि रिज़र्व बैंक ने अब अपनी मॉनिटरी पॉलिसी (मौद्रिक नीति) में “न्यूट्रल” (तटस्थ) रुख की जगह “अकॉमोडेटिव” (उदार) रुख अपनाया है। मूल बात यही है।

प्रमुख खिलाड़ी अब यह उम्मीद कर सकते हैं कि रिज़र्व बैंक की नीति भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दिशा में अधिक होगी, बजाय मूल्य के मोर्चे पर निगरानी रखने की अपनी मुख्य चिंता के। वर्तमान संदर्भ में शायद यह एक उचित रुख है, जबकि भारत की ग्रोथ रेट “निराशा” के दौर से उबरी है। रिज़र्व बैंक मौजूदा संदर्भ में महंगाई प्रबंधन से ज्यादा ग्रोथ को अधिक प्रोत्साहन देना चाहता है।

कम से कम दो कमजोरियां हैं, जिन्हें रिज़र्व बैंक ने अपेक्षाकृत स्थिर और सुविधापूर्ण के रुप में स्वीकार कर लिया है। पहली, भारत का सेवा निर्यात (सर्विसेज़ एक्सपोर्ट) और दूसरी, ग्लोबल फायनैंशियल मार्केट्स के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न वित्तीय अस्थिरता की संभावना।

ट्रंप के शुल्कों ने सेवा क्षेत्र (सर्विसेज़ एक्सपोर्ट) को ध्यान में नहीं रखा है और शुल्क मुख्य रुप से माल निर्यात पर लगाए गए हैं। अगर ट्रंप अचानक सेवाओं के निर्यात पर कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं, तो भारत को भारी झटका लग सकता है। हमारा माल निर्यात जी.डी.पी. का केवल 2 प्रतिशत है। सेवा निर्यात का हिस्सा कहीं अधिक है। सर्विसेज़ एक्सपोर्ट को कम करने वाला कोई भी कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को पैरलाइज़ कर सकता है, पंगु बना सकता है। वैसे भी भारत का सर्विसेज़ एक्सपोर्ट, आर्टिफिशल इन्टैलिजैंस की प्रगति के कारण, अस्तित्व का संकट झेल रहा है। इन निर्यातों में कई ऐसी सेवाएं हैं, जो एआई उपकरणों द्वारा दी जा सकती हैं, तथा निचले स्तर के सॉफ्टवेयर डवलपर्स और कोडर्स द्वारा किए गए काम को उपयोग में लिया जा सकता है।

कांग्रेस अधिवेशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि करीब-करीब यही कहानी शेष भारत की भी है। जहाँ मोदी ने जातिगत जनगणना के लिये सहमत होने से इनकार कर दिया है, वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जातिगत जनगणना हो।

मजे की बात यह है कि राहुल के भाषण के ज्यादतर हिस्से का निशाना मोदी और उनकी सरकार रहीं, लेकिन उन्होंने इस अवसर का उपयोग उस रोड मैप पर प्रकाश डालने के लिये नहीं किया कि वे चुनाव कैसे जीतेंगे तथा भाजपा को सत्ता से बाहर कैसे करेंगे।

उनका जोर केवल डीसीसी के प्रस्तावित सशक्तीकरण पर तथा यह सुनिश्चित करने पर रहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिये पार्टी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जमीनी स्तर से शुरु की जायेगी।

मल्लिकार्जुन खड़गे संगठन को मजबूत बनाने की बात कहते आ रहे हैं। उनका कहना था कि केवल संगठन की मजबूती ही पार्टी के बने रहने तथा आगे बढ़ते रहने में मददगार होती है।

सूत्रों का कहना है कि यह गांधी परिवार के अंदरुनी संकट का संकेत है।

253 सिख श्रद्धालु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाने का वीजा मिला है। उन्होंने बताया कि यह जत्था 10 अप्रैल को सुबह छह बजे वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। आधा समूह गुरुद्वारा पंजा साहिब और आधा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जायेगा।

उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को दोनों जत्थे ननकाना साहिब में एकत्र होंगे और 12, 13 और 14 अप्रैल को बैसाखी मनाएंगे। जो श्रद्धालु पहले पंजा साहिब गए हैं, वे करतारपुर साहिब जाएंगे और जो करतारपुर साहिब गए हैं, वे पंजा साहिब जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को यह जत्था लाहौर पहुंचेगा और वहां गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के बाद 19 अप्रैल को भारत वापस लौटेगा। सरदार दलजीत सिंह सरना को जत्थे का प्रभारी बनाया गया है।

‘बंगाल में वक्फ बिल लागू नही करेंगे’

प.बंगाल की मु.मंत्री ममता बनर्जी ने मुसलमानों से कहा, दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी

- **ममता बनर्जी ने कहा, हमारा संदेश है “जियो और जीने दो” अगर किसी को मेरी संपत्ति लेने का हक नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ दूसरे की संपत्ति ली जा सकती है।**

कोलकाता, 09 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जैन समुदाय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, और राज्य में एकता बनाए रखने की वकालत की। ममता ने अपने संबोधन में कहा कि हम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। मेरी सरकार धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देगी। मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं, मगर भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा।

टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बंगाल में “फूट डालो और राज करो” की नीति नहीं चलेगी। आपको “जियो और जीने दो” का संदेश देना चाहिए। बंगाल में रहने वालों को सुरक्षा देना हमारा काम है। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि अगर कोई आपको राजनीतिक रूप से इकट्ठा होने के लिए उकसाता है, तो कृपया ऐसा न करें। कृपया याद रखें कि दीदी आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। अगर हम साथ रहेंगे, तो हम दुनिया जीत सकते हैं।

सीएम बनर्जी ने आगे कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थानों पर क्यों जाती हूं। मैंने कहा कि मैं अपने पूरे जीवनकाल में वहां जाती रहूंगी। भले ही आप मुझे गोली मार दें, आप मुझे एकता से अलग नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, मेरा मानना है कि इसे अभी पारित नहीं किया जाना चाहिए था। बंगाल में विभाजन नहीं होगा, जियो और जीने दो। अगर किसी को मेरी संपत्ति लेने का अधिकार नहीं है, तो मैं कैसे कह सकती हूं कि किसी और की संपत्ति ली जा सकती है? हमें 30 फीसदी (मुसलमानों) को साथ लेकर चलना होगा। याद रखिए, दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगी।

उन्होंने आगे कहा कि हमारा मकसद जोड़ना है, बांटना नहीं। जब हम एकजुट रहेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। हमारी नीति है कि जियो और जीने दो। कुछ लोग बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं राज्य में हिंदू धर्म को संरक्षण नहीं देती। फिर सबको संरक्षण कौन देता है? मुझे बंगाल के अल्पसंख्यकों को श्रेय देना चाहिए, जो राज्य में हिंदू त्योहार भी मनाते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि यह बंगाल है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

पेपर लीक में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पाएगा। फतेहगढ़ एसडीएम हनुमानाराम के पकड़े जाने की सूचना से जिले में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है।

सूत्रों के अनुसार एस.आई. भर्ती परीक्षा में नरपत की जगह एस.डी.एम हनुमानाराम डमी परीक्षार्थी बनकर बैठे थे। हालांकि नरपत मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। बाकी जानकारी एस.डी.एम हनुमानाराम से पूछताछ के बाद सामने आ पायेगी।

26 राफेल विमान खरीदे जाएंगे

- **सरकार ने 63 हजार करोड़ रु. के इस सौदे को स्वीकृति प्रदान कर दी है।**

नयी दिल्ली, 09 अप्रैल। नौसेना को अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने फ्रांस से 63 हजार करोड़ रूपये की लागत से 26 मरीन राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सरकार ने मंगलवार को इन विमानों की खरीद को मंजूरी दी। इन लड़ाकू विमानों के मिलने के बाद नौसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ जायेगी। अभी वायु सेना के बेड़े में 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं।

सूत्रों ने बताया कि इस अनुबंध पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की संभावना है और विमानों की आपूर्ति में चार से पांच वर्ष का समय लग सकता है। अनुबंध के पैकेज में विमानों का रख रखाव, प्रशिक्षण और कलपुर्जों का देश में ही निर्माण भी शामिल है।

पैकेज़्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाया जाए

- **सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को तीन महीने में फैसला करने का निर्देश दिया।**

नई दिल्ली, 09 अप्रैल। पैकेज्ड फूट पर चेतावनी लेबल लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अगले तीन महीनों में सिफारिशों को लागू करे। एससी ने केंद्र से तीन महीने के भीतर एफएसएस लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 में संशोधन पर फैसला लेने को कहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पैकेज्ड फूड के पैकेट पर चेतावनी की मांग करने वाली जनहित में दायर याचिका पर ये टिप्पणी की है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आप सभी के पोते- पोतियां हैं? इस याचिका पर फैसला करने दें, आपको पता चल जाएगा कि कुरकुरे या मैगी क्या हैं और किस तरह का रैपर होना चाहिए। उन्हें पैकेट पर कोई जानकारी नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एफएसएसएआई को तीन महीने के भीतर नए नियम में संशोधन पूरा करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है।

भगोड़े कारोबारी माल्या पर भारतीय बैंकों की बड़ी जीत

भारतीय बैंकों की अपील पर ब्रिटेन के कोर्ट ने माल्या को दिवालिया घोषित किया

- **अब भारतीय बैंक माल्या की ब्रिटेन की सम्पत्ति बेचकर बकाया लोन वसूल कर सकते हैं।**

नई दिल्ली, 09 अप्रैल। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस वाले भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। एसबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंको के एक कंसोर्टियम ने माल्या के खिलाफ ब्रिटेन में दिवालियापन के आदेश को बरकरार रखने के लिए अदालती अपील का केस जीत लिया है।

इस तरह लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में भारतीय बैंकों को बड़ी जीत मिली है। भारतीय बैंक किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया लोन की अदायगी की मांग कर रहे हैं। भारतीय बैंकों ने ब्रिटेन के कोर्ट में माल्या को दिवालिया घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी, जिससे वे उनकी ब्रिटेन स्थिति संपत्तियों से अपने कर्ज की वसूली कर सकें। अब ब्रिटेन के कोर्ट ने भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

लंदन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंथनी मान ने भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जबकि विजय माल्या की तरफ से दायर अपील की अनुमति मांगने वाले दो आवेदनों को खारिज कर दिया है। माल्या को भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

न्यायमूर्ति मान ने कहा, बैंकों की दलील ऐसी थी, जिसे उन्हें स्वीकार करना ही था। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि दिवाला कार्यवाही का आदेश कायम है।

भारतीय बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म टीएलटी एलएलपी ने कहा कि इस फैसले से यह पुष्टि होती है कि बैंकों के पास माल्या की संपत्तियों पर कोई सुरक्षा नहीं है और दिवाला अर्जी सही थी। अदालत ने भी यह पाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गई संपत्तियों से प्राप्तियां सशर्त थीं और अंग्रेजी कानून के तहत कर्ज से मुक्ति नहीं देती थीं। टीएलटी एलएलपी के कानूनी निदेशक निक कर्लिंग ने कहा, यह बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है।

‘हम पनामा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनैतिक व आर्थिक धाराओं में भी यह बयान, जैसा कि यह सुनने में कड़ा लगता है, कार्रवाई का वादा नहीं, बल्कि एक रेखा खींचने का संकेत है। पनामा रेखा को माने या न माने, या उसे इसकी आवश्यकता है या नहीं- यह एक अलग सवाल है।

बिहार में बिजली गिरने से 15 की मौत

- **सूत्रों के अनुसार बेगुसराय, दरभंगा, मछुबनी व समस्तीपुर में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से ये हादसे हुए हैं।**

पटना, 09 अप्रैल। बिहार में बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में बुधवार को बिजली गिरने की घटना में 15 लोगों की झुलसकर मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों के अनुसार बेगूसराय और दरभंगा में पांच-पांच, मधुबनी में तीन और समस्तीपुर में दो व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हुयी है।

बेगूसराय से प्राप्त समाचार के अनुसार जिले में बिजली गिरने से मरने वाले पांच लोगों में एक महिला, एक तीन वर्षीय बालिका शामिल है। इसके अलावा एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। दरभंगा में भी 5 लोगों के मरने की खबर है। इनमें एक दस वर्षीय बालक व एक महिला भी शामिल है। मधुबनी में तीन लोगों के मरने की जानकारी मिली है। इनमें से एक 19 वर्षीय युवती है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908